प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मूल्यांकन

प्रासंगिकता: जीएस2: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन

की-वर्ड्स : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एएवाई, प्राथमिकता घरेलू, व्यापक और पारदर्शी अध्ययन, खाद्यान्न, कोविड-19, निःशुल्क संस्कृति, रूस-यूक्रेन युद्ध, खाद्य की वैश्विक आपूर्ति।

संदर्भ:हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और तीन महीने (अक्टूबर 2022-दिसंबर 2022) के लिए बढ़ा दिया है, जो गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने की योजना है।

मुख्य विचार:

- PMGKAY को अब तक छह चरणों में 3.45 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी मिली है।
- PMGKAY के चरण VII (अक्टूबर 2022-दिसंबर 2022) में 44,762 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी शामिल है।
- विस्तार के मौजूदा चरण के दौरान लगभग 122 लाख टन खाद्यान्न के अनुमानित खर्च को ध्यान में रखते हुए, कुल आवंटन लगभग 1,121 लाख टन होगा।

विस्तार पर चिंता:

- **फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा**
    - यह योजना मुफ़्त उपहारों की संस्कृति को बढ़ावा देती है और मुफ़्त उपहारों की संस्कृति के महत्व पर बहस चल रही है।
- **वित्तीय मुद्दे**

- जून में ऐसी खबरें आईं कि केंद्र के व्यय विभाग ने धन की कमी का हवाला देते हुए इसका पक्ष नहीं लिया।
- मौजूदा चरण के लिए ₹44,762 करोड़ के व्यय के साथ, PMGKAY का कुल व्यय लगभग ₹3.91 लाख करोड़ होगा।

- **गैर-महामारी के समय में प्रासंगिकता**
  - इसने यह भी विचार रखा कि इस तरह की योजना की अब "गैर-महामारी के समय" में आवश्यकता नहीं थी।
- **वैश्विक स्तर पर प्रभाव**
  - इसे फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष और दुनिया के खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- **राजनीतिक एजेंडा**
  - सत्तारूढ़ दल के आलोचकों का कहना है कि इस योजना का विस्तार क्रमश: हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

- **योजना के बारे में**
  - पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई), कोविड-19 संकट के कठिन समय के दौरान गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर परिवारों/लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई ताकि अनुपलब्धता के कारण उन्हें परेशानी न हो पर्याप्त खाद्यान्न की।
  - यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है।
- **सुविधाएँ**
  - इस कल्याणकारी योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (**एनएफएसए**) [**अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों**] के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जिसमें (डीबीटी) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के तहत शामिल हैं।
  - यह एनएफएसए के तहत नियमित मासिक कोटा से अधिक है, यानी एएवाई के लिए प्रति परिवार 35 किग्रा प्रति माह और पीएचएच (प्राथमिकता वाले परिवार) के लिए प्रति व्यक्ति 5 किग्रा प्रति माह।
  - लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आते हैं।

- **पीएमजीकेएवाई का प्रदर्शन:**
  - नीति निर्माता और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस योजना ने महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में बदलाव लाया। **उदाहरण के लिए,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय स्थायी समिति और आईएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्किंग पेपर, **"महामारी, गरीबी और असमानता: भारत से साक्ष्य"** (अप्रैल 2022) द्वारा इसकी सराहना

की गई है, जिसने निष्कर्ष निकाला है कि **"सामाजिक सुरक्षा तंत्र भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तार द्वारा प्रदान की गई महामारी के झटके के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर लिया।"**

आगे की राह :

- यह कहीं बेहतर होता अगर सरकार पीएमजीकेएवाई के प्रभाव के संबंध में एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना का विस्तार करने का निर्णय लेती, जैसा कि स्थायी समिति ने मार्च 2022 की रिपोर्ट में सुझाव दिया था।
    - केंद्रीय अधिकारियों को एक व्यापक और पारदर्शी अध्ययन शुरू करना चाहिए और इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक करना चाहिए।
- प्रस्तावित अध्ययन खाद्यान्न-ड्राइंग कार्ड धारकों के डेटाबेस को अद्यतन करने, डेटा की गंभीर रूप से जांच करने का आधार होना चाहिए
    - केंद्र को राज्यों को नियमित रूप से या कम से कम अत्यधिक रियायती दरों पर 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।
    - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से डायवर्जन की पुरानी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य के अधिकारियों को योजना की निरंतरता पर विचार करने की आवश्यकता है।
    - बजटीय आवंटन को नियंत्रण में रखने के लिए चावल या गेहूं के लिए कोटा पर नियमों को उपयुक्त रूप से बदला जा सकता है।

निष्कर्ष:

- **PMGKAY** वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है लेकिन विस्तार का निर्णय एक पारदर्शी और व्यापक निर्णय पर आधारित होना चाहिए।

स्रोत- द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

Q. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।
2. इस कल्याणकारी योजना के तहत, भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है।
3. यह एनएफएसए के तहत नियमित मासिक कोटा से अधिक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 3
b) 2 और 3 केवल
c) 3 केवल
d) 1, 2 और 3

उत्तर- **A.**

व्याख्या:

1. यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। **इस प्रकार कथन 1 सही है।**
2. इस कल्याणकारी योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) [**अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों**] के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत शामिल हैं। (डीबीटी)। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
3. यह एनएफएसए के तहत नियमित मासिक कोटा से अधिक है, यानी एएवाई के लिए प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा और पीएचएच के लिए प्रति व्यक्ति 5 किग्रा प्रति माह। **इस प्रकार कथन 3 सही है।**

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q: गरीबों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (**पीएमजीकेएवाई**) के प्रदर्शन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003